बिहार 18 लाख की रुकी पेंशन पर बड़ा फैसला, खाते में आएंगे पैसे!

विषय सूची (Table of Contents):

>> 1. बिहार में 18 लाख लोगों की रुकी हुई पेंशन का रास्ता साफ, सरकार का बड़ा ऐलान...
>> सामाजिक सुरक्षा पेंशन का व्यापक दायरा...
>> वंचित लाभार्थियों को मिलेगा शीघ्र लाभ...
>> 2. ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग है जरूरी, जिलाधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश...
>> ई-केवाईसी (e-KYC) और बैंक खाता आधार लिंकिंग...
>> जिलाधिकारियों की तय होगी जवाबदेही...
>> 3. राज्य के सभी 534 प्रखंडों में जन-कल्याण शिविर का हो रहा है विशेष आयोजन...
>> एक ही छत के नीचे सभी योजनाओं की सुविधा...
>> प्रशासनिक पारदर्शिता और ऑन-द-स्पॉट समाधान...
>> 4. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना एक महीने के भीतर बैंक खाते में आएगी लंबित राशि...
>> एक माह के भीतर डीबीटी भुगतान...
>> पारदर्शी भुगतान प्रणाली...
>> 5. बिहार में 1 करोड़ जीविका दीदियों को लखपति दीदी बनाने का नया लक्ष्य...
>> 48 लाख महिलाएं बन चुकी हैं लखपति...
>> अगले दो वर्षों में 1 करोड़ का नया लक्ष्य...
>> 6. फुलवारीशरीफ को करोड़ों की सौगात 73 योजनाओं का शिलान्यास और सड़क निर्माण का फ...
>> 73 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास...
>> नत्थूपुर सड़क से एम्स गोलम्बर कनेक्टिविटी व स्कूल अपग्रेडेशन...
>> 7. शिविर में आयुष्मान कार्ड से लेकर पीएम आवास योजना तक के लाभुकों को मिली बड़ी र...
>> प्रमुख योजनाओं के प्रमाण पत्र एवं चाबियों का वितरण...
>> जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति...
>> निष्कर्ष (Conclusion)...
>> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

Bihar Pension Welfare Scheme Latest Update 2026:बिहार सरकार ने राज्य के लाखों कमजोर वर्गों, वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के हित में एक ऐतिहासिक और राहत भरा कदम उठाया है। राज्य में तकनीकी कारणों एवं दस्तावेज सत्यापन के अभाव में रुकी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए कई अन्य महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़ी किसी भी योजना का लाभ बिचौलियों के बिना सीधे पात्र लाभार्थियों तक

पहुंचेगा। यदि आप भी बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension Scheme), महिला रोजगार योजना या अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का स्टेटस (Status Check) देखना चाहते हैं, तो इस विस्तृत रिपोर्ट में पूरी प्रक्रिया और सरकारी आदेशों की जानकारी प्राप्त करें।

1. बिहार में 18 लाख लोगों की रुकी हुई पेंशन का रास्ता साफ, स

बिहार के लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने उन 18 लाख से अधिक पात्र नागरिकों की पेंशन पुनः शुरू करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है, जिनका भुगतान पिछले कुछ समय से तकनीकी अड़चनों के कारण रुका हुआ था।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का व्यापक दायरा

राज्य में वर्तमान में 1 करोड़ 12 लाख परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में चिह्नित किया गया है। इनमें से 94 लाख परिवारों के पात्र सदस्यों को नियमित रूप से मासिक पेंशन राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से किया जा रहा है।

वंचित लाभार्थियों को मिलेगा शीघ्र लाभ

शेष 18 से 20 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनकी पहचान पूरी हो चुकी है, परंतु प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण उनकी राशि अटकी हुई थी। सरकार ने निर्देश दिया है कि बिना किसी अनावश्यक देरी के इन सभी वंचित लाभार्थियों के खातों में जल्द से जल्द बकाया पेंशन राशि ट्रांसफर की जाए।

2. ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग है जरूरी, जिलाधिकारियों को दिए

पेंशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वास्तविक लाभार्थियों तक आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कड़े निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलाधिकारियों (DM) को इस अभियान को मिशन मोड में पूरा करने को कहा गया है।

ई-केवाईसी (e-KYC) और बैंक खाता आधार लिंकिंग

पेंशन राशि अटकने का मुख्य कारण बैंक खाते से आधार लिंक न होना अथवा ई-केवाईसी प्रक्रिया का अधूरा रहना पाया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति का सत्यापन शिविरों के माध्यम से तुरंत पूरा कराया जाए ताकि किसी भी गरीब का हक न रुके।

>> घर-घर और शिविर सत्यापन:प्रशासनिक टीमें पंचायत स्तर पर वंचित परिवारों की पहचान करेंगी।

>> डीबीटी सक्रियता:बैंक खातों को आधार सीडिंग से जोड़कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सुगम बनाया जाएगा।

>> त्वरित भुगतान:सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होते ही पेंशन राशि का भुगतान स्वतः शुरू हो जाएगा।

जिलाधिकारियों की तय होगी जवाबदेही

सभी जिलों के डीएम को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में विशेष निगरानी रखें। यदि किसी पात्र व्यक्ति को दस्तावेज की कमी के कारण समस्या आती है, तो स्थानीय प्रशासन मौके पर ही उसका समाधान सुनिश्चित करेगा।

3. राज्य के सभी 534 प्रखंडों में जन-कल्याण शिविर का हो रहा

सरकारी सेवाओं को आमजन के घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार के सभी 534 प्रखंडों में प्रखंड सहयोग-सह-जन-कल्याण शिविर का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है।

एक ही छत के नीचे सभी योजनाओं की सुविधा

इन विशेष शिविरों का प्राथमिक लक्ष्य केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। अब ग्रामीणों को ब्लॉक या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप भी सरकारी योजनाओं से संबंधित नई पहल जैसेकेसीसी, आयुष्मान कार्ड, पेंशन व आवास योजनाओं की सौगातके तहत लगने वाले शिविरों का लाभ उठा सकते हैं।

प्रशासनिक पारदर्शिता और ऑन-द-स्पॉट समाधान

शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एक साथ उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट निराकरण कर रहे हैं।

आवेदन पत्रों का त्वरित सत्यापन, सुधार एवं नए पंजीकरण की व्यवस्था इन शिविरों में प्राथमिकता से की जा रही है।

4. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: एक महीने के भीतर बैंक खात

राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम मेंमुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाके तहत लंबित भुगतान को लेकर अहम घोषणा की गई है।

एक माह के भीतर डीबीटी भुगतान

योजना के अंतर्गत जिन पात्र महिला लाभार्थियों को अभी तक प्रोत्साहन अथवा सहायता राशि प्राप्त नहीं हो सकी थी, उनके लिए समयसीमा तय कर दी गई है। आगामी एक माह के भीतर सभी शेष लाभार्थियों के सीधे बैंक खातों में राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। यदि आप भी स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो फ्री लोन! पीएम मुद्रा योजना से 10 लाख तक का स्वरोजगार लोन, अभी आवेदन करेंकी सहायता से अपने व्यवसाय को गति दे सकते हैं।

पारदर्शी भुगतान प्रणाली

विभाग द्वारा पोर्टल पर लाभार्थी सूची (Beneficiary List 2026) को अपडेट किया जा रहा है ताकि महिलाएं घर बैठे अपना पेमेंट स्टेटस (Payment Status Check) ऑनलाइन देख सकें। इस पहल से लाखों महिलाओं को छोटे उद्यम शुरू करने में सीधी मदद मिलेगी।

5. बिहार में 1 करोड़ जीविका दीदियों को लखपति दीदी बनाने का

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकीं जीविका दीदियों के लिए सरकार ने अगले दो वर्षों का एक महत्वाकांक्षी विजन तैयार किया है। इसके तहत राज्यभर की महिलाओं की आय को स्थायी रूप से बढ़ाने की योजना है।

48 लाख महिलाएं बन चुकी हैं लखपति

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार में अब तक 48 लाख जीविका दीदियां लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं। उनकी वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों का जीवन स्तर सुधरा है।

अगले दो वर्षों में 1 करोड़ का नया लक्ष्य

सरकार ने आगामी 2 वर्षों के भीतर राज्य की 1 करोड़ जीविका दीदियों को लखपति दीदी बनाने का दृढ़ संकल्प लिया है। इसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और बाजार लिंकेज उपलब्ध कराया जाएगा। स्वरोजगार को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए उद्यमीबिना गारंटी 5 करोड़ तक लोन! सरकार की नई बिजनेस योजनाएंके जरिए भी आधुनिक उद्यम स्थापित कर सकते हैं।

6. फुलवारीशरीफ को करोड़ों की सौगात: 73 योजनाओं का शिलान्यास

पटना जिले के फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित जन-कल्याण समारोह में क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए कई ऐतिहासिक सौगातें दी गईं।

73 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास

फुलवारीशरीफ प्रखंड के इस्माईलपुर ढीबरा ग्राम पंचायत के नदियावां में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान 73 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कों, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित हैं।

नत्थूपुर सड़क से एम्स गोलम्बर कनेक्टिविटी व स्कूल अपग्रेडेशन

यातायात को सुगम बनाने के लिए नत्थूपुर सड़क को सीधे एम्स (AIIMS) गोलम्बर से जोड़ने की घोषणा की गई है। इस बाईपास कनेक्टिविटी से क्षेत्र में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त, नदियावां स्थित मध्य विद्यालय को अपग्रेड करप्लस टू (2) हाई स्कूलका दर्जा देने की औपचारिक घोषणा की गई, जिससे स्थानीय छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

7. शिविर में आयुष्मान कार्ड से लेकर पीएम आवास योजना तक के ला

कार्यक्रम के दौरान हजारों लाभार्थियों को विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया गया, जिससे ग्रामीण समाज में व्यापक उत्साह देखने को मिला।

प्रमुख योजनाओं के प्रमाण पत्र एवं चाबियों का वितरण

शिविर मंच से वरिष्ठ मंत्रियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं के दस्तावेज और लाभ वितरित किए गए:

>> स्वास्थ्य सुरक्षा:मुफ्त इलाज के लिए पात्र परिवारों कोआयुष्मान कार्डप्रदान किए गए।

>> आवास का सपना:प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)के लाभार्थियों को नवनिर्मित पक्के मकानों की सांकेतिक चाबी सौंपी गई।

>> कृषि व ऊर्जा:पीएम किसान सम्मान निधिऔरपीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाके प्रमाण पत्र दिए गए।

>> बालिका कल्याण:मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनाके तहत वित्तीय सहायता के सांकेतिक चेक वितरित किए गए।

जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति

समारोह में उपमुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री, स्थानीय विधायकों एवं विधान पार्षदों ने भी जनता को संबोधित किया और सरकार की जन-समर्थक नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

निष्कर्ष (Conclusion)

बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 18 लाख वंचितों की समस्याओं का त्वरित समाधान, प्रखंड स्तर पर जन-कल्याण शिविरों का आयोजन और 1 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य राज्य के समावेशी विकास को दर्शाता है। ई-केवाईसी और आधार सीडिंग के माध्यम से व्यवस्था को पारदर्शी बनाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी खजाने का हर एक रुपया सीधे जरूरतमंद नागरिकों तक पहुंचे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था, उनकी पेंशन रुकी हुई थी। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल सत्यापन पूरा कराकर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।

लाभार्थी अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय में आयोजित जन-कल्याण शिविर , सीएससी (CSC) केंद्र या अपने बैंक शाखा में जाकर आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक ई-केवाईसी सत्यापन करवा सकते हैं।

बिहार में कुल 1 करोड़ 12 लाख चिह्नित परिवारों में से लगभग 94 लाख परिवारों के पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान मिल रहा है।

राज्य के सभी 534 प्रखंडों में आयोजित इन शिविरों का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देना और मौके पर ही पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ना है।

मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, योजना के तहत जिन महिलाओं को अब तक सहायता राशि नहीं मिल सकी है, उन्हें आगामी एक महीने के भीतर सीधे बैंक खाते में राशि भेज दी जाएगी।

राज्य में 48 लाख महिलाएं पहले ही लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार का नया लक्ष्य अगले दो वर्षों के भीतर 1 करोड़ जीविका दीदियों को लखपति दीदी बनाकर आत्मनिर्भर बनाना है।

फुलवारीशरीफ में 73 विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ, नत्थूपुर सड़क को एम्स गोलम्बर से जोड़ने का निर्णय लिया गया और नदियावां मध्य विद्यालय को प्लस टू स्कूल में अपग्रेड किया गया।

शिविरों में आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, लखपति दीदी और पीएम आवास योजना के लाभ दिए जा रहे हैं।